निपटारा न हो जाए। एक निर्वाचन अर्जी जम्मू-कश्मीर में सफाकदल सभा-निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की बाबत भी लम्बित है। इस मामले में उप-निर्वाचन, उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा रोक दिया गया है। इस रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन तब ही कराया जा सकता है जब कि इस रोक को उच्च न्यायालय द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाए। लोक सभा में की रिक्तियों की और राज्य विधान सभाओं में के शेष स्थानो की बाबत उप-निर्वाचन निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षित होते ही करा लिए जाएंगे। राज्य सभा की दो रिक्तियां तब भरी जाएंगी जब संपृक्त राज्य विधान सभाएं अगली बार समवेत होंगी।

दिल्ली के गोदामों में मानव उपभोग के अयोग्य दूध का पाउडर

610. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :
श्री कं० हलदार :
श्री क० कि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ गोदामों में बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ दूध का पाउडर मानव उपभोग के अयोग्य पाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है और इस नुकसान के लिये उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) 1966-67 के दौरान 1.181 टोन्ज आयातित सपरेटा पाउडर मानव उपभोग के लिए अयोग्य पाया गया और चालू वर्ष 1967-68 के दौरान अब तक 9 टोन्ज अयोग्य पाया गया है।

(ख) दिल्ली दुग्ध-योजना भारी मात्रा में आयातित सपरेटा पाउडर काम में लाती है। भारी मात्रा को सम्भालते समय बिखरने और मौसम की खराबी के कारण कुछ दुग्ध चूर्ण को बेकार होने से रोका नहीं जा सकता।

(ग) मात्रा थोड़ी है और हानि भी सामान्य रूप में है। किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा खाद्यान्न की सप्लाई

611. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन

दिया है कि आंध्र प्रदेश दक्षिण के कमी वाले राज्यों को अधिक खाद्यान्न देगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई पूर्व शर्तें और प्रस्ताव रखे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) से (ग). अप्रैल, 1967 में नई दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बतलाया था कि 1966-67 में आंध्र प्रदेश से चावल के निर्यात का लक्ष्य (1965-66 में चावल निर्यात की गई लगभग 2.77 लाख मीटरी टन की मात्रा के मुकाबले में) 6 लाख मीटरी टन होगा । उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त 6 लाख मीटरी टन चावल का निर्यात इस बात पर आधारित था कि भारत सरकार 2 लाख मीटरी टन गेहूं और माइलो आंध्र प्रदेश को दे ।

Foodgrains Prices

***612. Shri P. Ramamoorthy:**
Shri P. Gopalan:
Shri A. K. Gopalan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the former Union Food Minister had given categorical assurance to the nation at the time of devaluation that the cost of foodgrains would not be affected by the devaluation of the rupee; and

(b) if so, whether the devaluation has made any impact on the prices of foodgrains since that assurance had been given?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) It has not been possible to trace any such assurance given to the nation by the former Union Food Minister. However, on the devaluation of the Rupee on the 6th June, 1966, the Government had taken a decision not to raise the issue prices of foodgrains issued from the Central stocks even though the cost of foodgrains had gone up considerably consequent upon devaluation.

(b) The issue prices of foodgrains supplied from Central stocks were maintained at the pre-devalua ion level until November-December, 1966, when the issue prices of foodgrains were raised in order to reduce the quantum of subsidy borne by the Government. In the case of market prices of foodgrains, there has been some rise after devaluation which is also at ributable to successive poor harvests during the last two seasons.

National Highway No. 34

***613. Shri Tridib Kumar Chaudhuri:**
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact hat the work of widening and strengthening of National Highway No. 34, which provides the only road link between the port of Calcutta and Assam through North Bengal, has been held up due to delay in sanctioning the revised cost estimates; and

(b) the total amount sanctioned for the widening and strengthening of this National Highway and the amount spent so far?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No Sir.

(b) Thirteen estimates, aggregating Rs. 111.09 lakhs for widening and strengthening of this National Highway, have been sanctioned. An expenditure of Rs. 62.13 lakhs has been booked on these works up o the end of 1965-66.

Foodgrains Supply to Kerala

***614. Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri C. K. Chakrapani: